हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI:-UPHIN/201564743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 275 लखनऊ, बुधवार 17 जून 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

बिना डॉक्टर पर्चे नहीं मिलेगा कफ सिरप, सरकार सख्त, नए नियम लागू

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। देश में धड़ल्ले से बिक रहे कफ सिरप को लेकर अब केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का सिरप, खासकर खांसी के सिरप, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेचा जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा। बिना पर्चे के सिरप बेचने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत बदलाव किया है। इस संशोधन में "सिरप शब्द को सूची से हटा दिया गया है, जिससे अब ये दवाएं ओवर द काउंटर कैटेगरी में

सत्यमेव जयते
Ministry of Health
Government of India

नहीं रहेंगी। सरकार का यह फैसला कफ सिरप के दुरुपयोग, मिलावट और खासकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाल के दिनों में कफ सिरप से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें बच्चों की मौत के मामले भी शामिल हैं। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दवा निर्माण और बिक्री में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देशभर में दवा फैक्ट्रियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस बैठक में 200 से अधिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए थे। सरकार इस नए नियम की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी, ताकि इसके प्रभाव और पालन सुनिश्चित किया जा सके।

साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने देश भर में साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध करने में शामिल एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई केरल की रहने वाली एक महिला से हुई दो लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत की जांच के दौरान की गई। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि ध ोखाधड़ी की रकम एक खाते में जमा की गई थी, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के पैसों के लेनदेन के लिए हो रहा था। कुमार ने बताया कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए

एक टीम का गठन किया गया जिसने वित्तीय और तकनीकी विश्लेषण के जरिये इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद आरोपी उनके एटीएम कार्ड, चेक बुक, पंजीकृत मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग संबंधी जानकारी अपने कब्जे में ले लेते थे और इन्हें साइबर अपराधियों को दे देते थे। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय कुमार, प्रदीप कुमार, यतेंद्र कुमार, मुकेश, विनेश, गुरबाज सिंह, अमन, सूरज यादव, गौरव नाहर और लक्ष्मण के रूप में हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, नीट अभ्यर्थियों को बस किराये में मिलेगी 50% छूट

मोहर्रम मातम का अवसर, शक्ति प्रदर्शन का नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मोहर्रम में हथियार प्रदर्शन और कानफोडू डीजे पर प्रतिबंध, तय सीमा से अधिक नहीं होगी ताजिया की ऊंचाई

प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : मुख्यमंत्री योगी

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के हर कार्यक्रम में होगी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति, 20 जून को चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी मोहर्रम को लेकर कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि यह मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कानफोडू डीजे, ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने शांति भंग करने के प्रयासों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा भी की। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मोहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संवाद स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की घटना न होने पाए। पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानफोडू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम के जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा 10 से 12 फीट से अधिक ऊंची ताजियों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। साथ ही अन्य जनपदों में परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास ठहरने की व्यवस्था न हो, आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने एनटीए के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर अफवाह, भ्रामक अथवा गलत सूचनाएं प्रसारित करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों

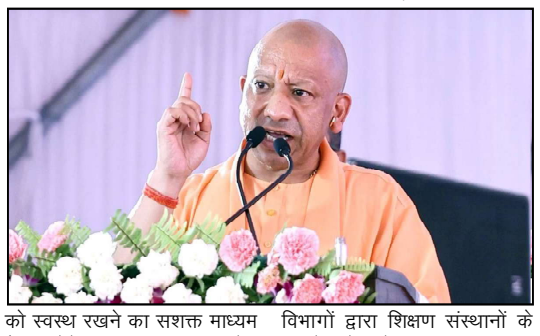

को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा इस वर्ष 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेशभर में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास को प्राथमिकता देने तथा नगरीय क्षेत्रों के 14 हजार वार्डों में कार्यक्रम स्थलों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने 20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों द्वारा शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, पुलिस बल की नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने तथा सभी पुलिस लाइनों एवं पीएसी बटालियनों को योग दिवस कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों, योग संस्थानों, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला, तहसील, विकासखंड मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा जनजागरूकता के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा प्रत्येक आयोजन में जनप्रतिनिधि अथवा शासन के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों एवं पुलिस लाइनों में भी योग कार्यक्रम आयोजित करने पर बल देते हुए इसे जनहित एवं जनसहभागिता का व्यापक अभियान बताया। जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों में निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे जिलों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, अन्यथा उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां अगले तीन दिनों में अनिवार्य रूप से सीएमओ की तैनाती करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि फील्ड में तैनाती केवल मेरिट पर होनी चाहिए। बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने नया भारत निर्माण के 12 साल पूरे होने पे दोहराया नयी पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। नया भारत निर्माण के 12 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पिछले दशक में देशभर में रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही, उन्होंने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने नया भारत निर्माण के 12 साल हैशटैग के साथ एक्स पर लिखा, पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। विकसित भारत के अपने विजन को साकार करने के लिए देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने मेरी सरकार का एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें पिछले 12 वर्षों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी उपलब्धियों को बताया गया है। मेरी सरकार की पोस्ट में कहा गया, किसी देश की ताकत लोगों, बाजारों और अवसरों को जोड़ने की उसकी क्षमता

से झलकती है। पिछले 12 वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आए बदलाव ने आवाजाही को तेज किया है, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है और विकास के नए रास्ते खोले हैं। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल दूरियों को कम कर रही है बल्कि अवसरों का विस्तार भी कर रही है और एक अधिक समृद्ध भारत की नींव को मजबूत कर रही है। मेरी सरकार एक्स पोस्ट के अनुसार, पिछले 12 सालों में भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। नेशनल हाईवे की लंबाई 91,287 किमी से बढ़कर 1,46,572 किमी हो गई है, जबकि हाईवे बनाने की रफ्तार लगभग तीन गुना बढ़कर 12 किमी प्रति दिन से 34 किमी प्रति दिन हो गई है। इस दौरान 55,000 किमी से ज़्यादा हाईवे जोड़े गए हैं, जिससे पूरे देश में आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में काफी तेजी आई है। एक अन्य पोस्ट में भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से हो रहे विस्तार पर भी जोर दिया गया। इसमें बताया गया है, ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 में 20 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 99.6 प्रतिशत हो गया है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क में से एक बन गया है। कुल 69,873 रूट किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जबकि 25 राज्यों ने 100 प्रतिशत रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लिया है। इसके अलावा, 1,330 से ज़्यादा अमृत भारत स्टेशनों को विकसित और आधुनिक बनाया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह भी बताया कि वंदे भारत ट्रेनों ने बेहतर स्पीड, आराम और कुशलता के साथ रेल यात्रा को बदल दिया है। अभी, 274 जिलों में 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान इन सेवाओं में लगभग चार करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो सालाना 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों ने लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है। इनमें पूरी ऑक्यूपेंसी (सीटें भरने की दर) देखी गई और सेवा शुरू होने के सिर्फ तीन महीनों के भीतर 1.2 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की। शहरी परिवहन में भी बड़ा बदलाव आया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1,155 किलोमीटर हो गया है। मेट्रो सेवाएं, जो 2014 में सिर्फ पांच शहरों में उपलब्ध थीं, अब 26 शहरों में चल रही हैं। रोजाना यात्रियों की संख्या 28 लाख से बढ़कर एक करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जिससे शहरी आवाजाही में काफी सुधार हुआ है। पोस्ट में उड़ान योजना की उपलब्धियों पर भी जोर दिया गया, जिसने हवाई यात्रा को ज़्यादा आसान और सस्ता बना दिया है। चालू एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई है, जबकि 663 उड़ान रूट अब 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वॉटर एयरोड्रोम को जोड़ते हैं। इन बदलावों ने लास्ट-माइल हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बनने में मदद की है।

टैंकर की टक्कर, सड़क पर बिखरीं लाशें

अस्पताल में मां ने भी तोड़ा दम, एक ही झटके में उजड़ गया पूरा परिवार

बीएनई

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मंगलवार सुबह टैंकर और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब 7 बजे रामकोला थाना क्षेत्र के खोटही निर्भया ग्राम के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि कप्तानगंज की ओर से आ रही मोटरसाइकिल की नेबुआ की तरफ से आ रहे टैंकर से आमने-सामने की टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे में मोटरसाइकिल सवार रामलखन मद्धेशिया (38) और उनके बेटे रौनक मद्धेशिया (11) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रामलखन की पत्नी शशिकला (35) और बेटी लाडो (14) को इलाज के लिए कप्तानगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शशिकला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, गंभीर रूप से घायल लाडो को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खड्डा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सत्ता की चाबी हाथ में ले ओबीसी समाज, मायावती ने कहा दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इस्तेमाल किया

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी समाज से बसपा का साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी समाज पूर्ण बहुमत दिलाकर बसपा की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों ने ओबीसी समाज को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि बसपा ने ही उन्हें सत्ता और संगठन दोनों में सच्ची भागीदारी दी। बसपा प्रमुख मायावती पिछले कई दिनों से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लगातार बैठकें कर रही हैं। इन बैठकों में उन्होंने ओबीसी भाईचारा कमेटी को दिए गए दिशा-निर्देशों की जमीनी तैयारियों,

जनाधार बढ़ाने और कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा की। मायावती ने कहा, "पिछले तमाम अनुभवों के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण बसपा व बहन मायावती की सरकार में ही निहित है।" उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ जाकर देख चुका है। उन पार्टियों ने न तो संगठन में और न ही सरकार में ओबीसी समाज को कभी आगे बढ़ाया या पर्याप्त भागीदारी दी। मायावती ने आरोप लगाया कि बसपा को छोड़कर अन्य पार्टियां ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को तभी आगे बढ़ाती हैं, जब उन्हें चुनावी लाभ चाहिए होता है। लेकिन पूरे ओबीसी समाज का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कभी भी उनके एजेंडे में नहीं रहा। बसपा प्रमुख ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण संबंधी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का इन पार्टियों ने खुलकर विरोध किया था। आजकल की सरकारें आरक्षण को निष्क्रिय बनाने के लिए संविदा और ठेके की नौकरियां दे रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मंडल रिपोर्ट लागू कराने में बसपा ने सबसे अधिक प्रयास किए। बसपा सरकार में ओबीसी समाज को उनका वाजिब हक दिया गया। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज के महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु आदि को बसपा ने पूरा सम्मान दिया।

राजनाथ सिंह के घर पर भाजपा की बड़ी बैठक, पार्टी की केंद्रीय टीम में बदलाव की अटकलें तेज

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भाजपा की केंद्रीय टीम में फेरबदल की अटकलों के बीच सोमवार को पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस के अरुण कुमार भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक चार घंटे से अधिक चली। हालांकि ,पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में पार्टी की केंद्रीय टीम में संभावित फेरबदल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन के नेतृत्व में नई केंद्रीय टीम की घोषणा इस महीने होने की संभावना है, जिसमें वरिष्ठ और युवा नेताओं का संतुलन देखने को मिल सकता है।

माफिया सफाया पसंदीदा विषय - योगी

9 साल में पहली बार सीएम ने बताई बात

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डी 3 त्रिवेणी कार्यक्रम में बताया कि माफिया सफाया पसंदीदा विषय है। पिछले 9 सालों में पहली बार था जब सीएम योगी ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि माफिया का सफाया करना ही उनका सबसे प्रिय विषय है। यूपी सीएम ने कहा कि 9 साल पहले लखनऊ में पुलिस की जमीन पर माफिया का कब्जा था। ये सब पिछली सरकारों के संरक्षण में चल रहा था लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस जमीन को खाली करवाया जा सके लेकिन यूपी सरकार ने जमीन खाली भी करवाई और उस पर भव्य फारेंसिक इंस्टीट्यूट भी बनवाया। लखनऊ का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट एफएसएल और साइबर सिक्योरिटी का केंद्र ही नहीं बल्कि वह आज के समय की सभी टेक्नॉलोजी का केंद्र भी है। वहां डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी चल रहे हैं। जिस जमीन पर ये बना था वह यूपी पुलिस की थी लेकिन उस पर कब्जा था एक कुख्यात माफिया का। 2017 में एक दिन उनके मन में यह ख्याल आया कि यूपी इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य है, हमारे पास केबल चार ही एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक लैब हैं, आखिर इतना बड़ा प्रदेश कैसे चलेगा।जो जांच भेजते हैं तो कई-कई साल लगते हैं। जब वह पूछते थे कि नई लैब क्यों स्थापित नहीं हो रहीं तो पता चलता था कि मैंन पावर नहीं है।उन्होंने आदेश दिया कि इंस्टीट्यूट स्थापित करो और अच्छा पैकेज दो। हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं होगा। यूपी के डीजीपी रिटायरमेंट के समय में एक फाइल लेकर उनके पास आए। मैंने पूछा ये क्या है,मुझे लगा कि हो सकता है कि एक्सटेंशन का लेकर आए हों। उन्होंने कहा कि आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की एक जमीन पर माफिया का कब्जा है तो मैंने कहा कि ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है।उन्हों ने हंसकर पूछा कि क्या मतलब।मैंने कहा कि ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। डीजीपी ने कहा कि एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किमी की दूरी पर 120 एकड़ की जमीन है, कीमत भी बहुत है। माफिया ने प्लॉटिंग शुरू कर दी है। मैंने उसके कागज निकाले और पूछा कि रेलवे बोर्ड के किस अधिकारी ने किसके पक्ष में इसे कब दिया था। उसकी पूरी कुंडली निकालो। कुंडली निकालकर बोर्ड के चेयरमैन को बुलाकर मैंने इस जमीन पर स्टे लगवाने की बात कही। वो हाई कोर्ट गए तो

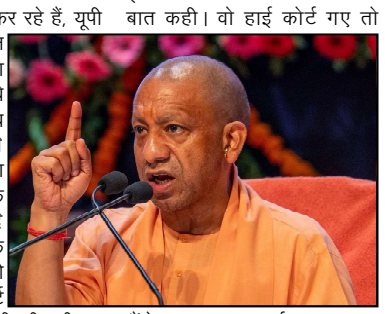

मैंने इधर एफआईआर करवा दी।अगले ही दिन वहां पर हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। माफिया से जमीन खाली करवाकर वहां पर फारेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब इस जमीन पर छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

संपादकीय

महंगाई का बढ़ता साया

भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में महंगाई केवल एक आर्थिक शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के दैनिक जीवन से जुड़ी एक ऐसी वास्तविकता है जो उनकी आय, बचत, भोजन, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं को सीधे प्रभावित करती है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों और बाजार के रुझानों से स्पष्ट है कि मार्च के बाद से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तेल, साबुन, डिटर्जेंट, कॉफी, हैंडवॉश, नमकीन, शैंपू और दालों जैसे आवश्यक उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि ने आम उपभोक्ता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। इन वर्गों की आय सीमित होती है और उनके खर्च का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक जरूरतों पर खर्च होता है। जब रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो इनके पास बचत के अवसर कम हो जाते हैं। परिणामस्वरूप परिवारों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है या फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेलों की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। जहां जून में इनमें 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं मार्च के बाद अब तक यह वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। भारत खाद्य तेलों की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार–चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और परिवहन लागत में वृद्धि ने खाद्य तेलों को महंगा बना दिया है। महंगाई का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल भी महंगे हुए हैं। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जब ईंधन महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। इसका असर खेतों से मंडियों तक, फैक्ट्रियों से बाजारों तक और गोदामों से उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर दिखाई देता है। फलस्वरूप लगभग हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आज कंपनियां भी बढ़ती लागत के दबाव में हैं। कच्चे माल, बिजली, परिवहन और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में कंपनियां दो तरीके अपनाती हैं या तो उत्पादों के दाम बढ़ाती हैं या पैकेट का आकार घटा देती हैं। उपभोक्ताओं को अक्सर यह महसूस नहीं होता कि समान कीमत पर मिलने वाला उत्पाद अब पहले से कम मात्रा में उपलब्ध है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में "श्रिंकफ्लेशन" कहा जाता है। यह भी महंगाई का एक छिपा हुआ रूप है। महंगाई का सबसे स्पष्ट असर रसोई पर दिखाई देता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार का मासिक रसोई बजट यदि पहले 15 हजार रुपये था तो कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह खर्च अब 17 से 18 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन सालभर में यह अतिरिक्त खर्च हजारों रुपये तक पहुंच जाता है। जिन परिवारों की आय स्थिर है, उनके लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। खेती में डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की लागत बढ़ने से कृषि उत्पादन महंगा हुआ है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, जबकि उपभोक्ता को वही उत्पाद महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। इस प्रकार महंगाई का बोझ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर पड़ता है, जबकि बीच की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संरचना अधिक लाभ अर्जित करती है। महंगाई का सामाजिक प्रभाव भी गहरा होता है। जब आवश्यक वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवार सबसे पहले मनोरंजन, पर्यटन और विलासिता के खर्च में कटौती करते हैं। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ने लगता है। कई परिवार बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी भविष्य की मानव पूंजी को प्रभावित करती है। आर्थिक दृष्टि से नियंत्रित महंगाई को विकास का संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे मांग और उत्पादन में वृद्धि का संकेत मिलता है। लेकिन जब महंगाई आय वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो यह आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। वर्तमान स्थिति में यही चिंता सामने आ रही है। वेतन और रोजगार की वृद्धि दर उतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे वास्तविक क्रय शक्ति कम हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर कदम उठाते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन, आयात शुल्क में कमी, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर निगरानी और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपाय किए जाते हैं। हालांकि वैश्विक परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भू–राजनीतिक तनावों के कारण कई बार इन प्रयासों का प्रभाव सीमित रह जाता है।

भारत–बांग्लादेश संबंधों में बढ़ता अविश्वास

– डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की कूटनीति में विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने जिस प्रकार राजनीतिक, सैन्य और मानवीय सहयोग प्रदान किया, उसने दोनों देशों के बीच मैत्री और विश्वास की मजबूत नींव रखी। पिछले पाँच दशकों में व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, संपर्क, जल संसाधन और सांस्कृतिक आदान–प्रदान जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की ष्पड़ोसी प्रथमष नीति तथा बांग्लादेश की विकासोन्मुख विदेश नीति ने भी संबंधों को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव और अविश्वास के संकेत दिखाई दिए हैं। यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध केवल रणनीतिक हितों से संचालित नहीं होते, बल्कि उनमें संवेदनशीलताओं, जनभावनाओं और पारस्परिक सम्मान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत और बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध मौजूद हैं। पिछले एक दशक में भूमि सीमा समझौता, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा व्यापार तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बांग्लादेश आज भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। हाल के समय में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हुए बदलावों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की भूमिका को लेकर अलग–अलग धारणाएँ विकसित हुई हैं। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक समूहों में यह धारणा बनी कि भारत किसी विशेष राजनीतिक शक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति

रखता है, जबकि भारत अपनी ओर से स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देने की बात करता रहा है। इस प्रकार की धारणाएँ चाहे तथ्यात्मक रूप से सही हों या नहीं, वे विश्वास के वातावरण को प्रभावित करती हैं और संबंधों में मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न करती हैं। तीस्ता नदी के जल बँटवारे का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी का जल कृषि और आजीविका की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से प्रस्तावित समझौता विभिन्न कारणों से लंबित है, जिससे बांग्लादेश में यह भावना विकसित हुई है कि उसकी चिंताओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका भी इस विषय को जटिल बनाती है, लेकिन समाधान में देरी ने अविश्वास को बढ़ावा दिया है। जल संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन के बिना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण कठिन प्रतीत होता है। सीमा संबंधी मुद्दे भी संबंधों में तनाव का कारण बने हैं। तस्करी, अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों के कारण कई बार सीमा पर अप्रिय घटनाएँ हुई हैं। नागरिक हताहतों की घटनाओं ने बांग्लादेश में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है और भारत की छवि पर भी प्रभाव डाला है। यद्यपि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ समन्वय बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं, फिर भी ऐसी घटनाएँ आम लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएँ पैदा करती हैं। पड़ोसी देशों के बीच सीमा केवल सुरक्षा का विषय नहीं होती, बल्कि मानवीय और सामाजिक संबंधों से भी जुड़ी होती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसे मुद्दों ने भी बांग्लादेश में कुछ आशंकाएँ उत्पन्न कीं। यद्यपि भारत ने बार–बार स्पष्ट किया कि ये उसकी आंतरिक नीतियाँ हैं, फिर भी बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त की गई कि इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीतियों की वास्तविकता के साथ–साथ उनकी सार्वजनिक धारणा भी महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि ऐसे मुद्दे कभी–कभी कूटनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता भी भारत–बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बांग्लादेश ने अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन सहित कई देशों के साथ आर्थिक और अवसंरचनात्मक सहयोग बढ़ाया है। भारत के लिए यह स्वाभाविक चिंता का विषय है कि क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति का अत्यधिक प्रभाव उसके रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखते हुए विभिन्न देशों से निवेश और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना चाहता है। इस स्थिति में दोनों देशों के लिए पारदर्शिता और संवाद अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। व्यापारिक असंतुलन भी अविश्वास के कारकों में शामिल है। यद्यपि द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका लाभ अपेक्षाकृत अधिक भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। बांग्लादेश लंबे समय से भारतीय बाजार में अपने उत्पादों की बेहतर पहुँच तथा गैर–शुल्क बाधाओं में कमी की मांग करता रहा है। आर्थिक संबंधों में असंतुलन की भावना यदि लंबे समय तक बनी रहे तो वह राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आर्थिक साझेदारी को अधिक संतुलित और समावेशी बनाना समय की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने भी संबंधों को प्रभावित किया है। आज गलत सूचनाएँ, भ्रामक प्रचार और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री बहुत तेजी से फैलती है। कई बार छोटी घटनाएँ भी डिजिटल मंचों पर बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे वातावरण में सरकारों और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे तथ्यपरक संवाद को बढ़ावा दें और दुष्प्रचार पर प्रभावी नियंत्रण रखें। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों और पड़ोसी देशों की संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित करे। एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति होने के कारण भारत की नीतियों का प्रभाव उसके पड़ोसियों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इसलिए केवल राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है; पड़ोसी देशों की आशंकाओं और अपेक्षाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा चिंताएँ, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों को एक–दूसरे की वैध चिंताओं का सम्मान करना होगा। विश्वास बहाली के लिए सबसे पहले लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में ठोस पहल आवश्यक है। तीस्ता जल समझौते को प्राथमिकता देकर दोनों देश एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। सीमा प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना, संयुक्त गश्त और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना भी आवश्यक है। व्यापारिक असंतुलन को कम करने के लिए बांग्लादेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। ऊर्जा, परिवहन और संपर्क परियोजनाओं को गति देकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक परस्पर निर्भर बनाया जा सकता है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को नियमित और संस्थागत स्वरूप देना भी आवश्यक है। जब देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच निरंतर संवाद बना रहता है, तब गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। साथ ही शिक्षा, संस्कृति, खेल, मीडिया और पर्यटन के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना चाहिए। सरकारों के बीच विश्वास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नागरिकों के बीच विश्वास भी है। सांस्कृतिक निकटता दोनों देशों की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय मंचों जैसे बिंस्टेक् और बीबिन के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना भी उपयोगी होगा। साझा आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग अविश्वास को कम करने में सहायक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास दोनों देशों को और निकट ला सकते हैं। अंततः भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो देशों के बीच की साझेदारी नहीं हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, भाषा, भूगोल और साझा संघर्षों से निर्मित एक विशेष संबंध हैं। हाल के वर्षों में उत्पन्न तनाव और अविश्वास यह अवश्य दर्शाते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में संवेदनशीलताओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। संवाद, सहयोग, पारस्परिक सम्मान और साझा विकास की भावना के आधार पर दोनों देश वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। यदि भारत और बांग्लादेश विश्वास की नई नींव पर अपने संबंधों का पुनर्निर्माण करते हैं, तो न केवल द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होंगे, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग भी अधिक प्रशस्त होगा।

वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की परीक्षा

–किशन सनमुखदास भावनानी

अमेरिका ईरान तनाव–संभावित समझौते को लेकर परस्पर वैश्विक स्तरपर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वित्तीय बाजार केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि भू– राजनीतिक घटनाओं से भी संचालित हो रहे हैं।अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव तथा युद्धविराम एवं संभावित समझौते को लेकर परस्पर विरोधी दावों ने विश्व निवेशकों को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। एक ओर अमेरिका बार–बार यह संकेत दे रहा है कि 14 जून 2026 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है,वहीं दूसरी ओर ईरान इसे केवलप्रारंभिक वार्ता बताते हुए अपनी शर्तें पूरी न होने की बात कह रहा है। ईरान के भीतर भी संभावित समझौते के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस अनिश्चित वातावरण का सीधा प्रभाव वैश्विक पूंजी प्रवाह,निवेशक विश्वास और शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के 14 जून 2026 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून 2026 के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से 62,853 करोड़ रूपए की भारी निकासी की है। यह केवल भारतीय बाजार की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक पूंजी के बदलते रुझानों, जोखिम की बढ़ती धारणा और निवेशकों की सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर वापसी का संकेत हैं विदेशी निवेशकों की यह बिकवाली किसी एक कारण का परिणाम नहीं है,बल्कि अनेक वैश्विक और घरेलू कारकों का संयुक्त प्रभाव है।सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति मानी जा रही है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और वहां ब्याज दरों के उच्च स्तरपर बने रहने से वैश्विक निवेशकों को सुरक्षित और निश्चित प्रतिफल के अवसर उपलब्ध हो रहेहैं।सामान्यत:जब अमेरिका में जोखिम– रहित प्रतिफल बढ़ता है तो उभरते बाजारों, विशेषकर भारत जैसे देशों में निवेश का आकर्षण कुछ कम हो जाता है। साथियों, विदेशी फंड प्रबंधक जोखिम लेकर उभरते बाजारों में निवेश करने के बजाय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड तथा डॉलर आधारित परिसंपत्तियों में धन लगाना अधिक सुरक्षित समझते हैं। परिणामस्वरूप भारत सहित कई उभरते बाजारों से पूंजी निकासी तेज हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ती भू–राजनीतिक अस्थिरता है। अमेरिका–ईरान तनाव, तेल आपूर्ति मार्गों को लेकर चिंताएं, ऊर्जा कीमतों में संभावित उतार–चढ़ाव और वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कम किया है। जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध या संघर्ष की आशंका बढ़ती है, निवेशक तथाकथित ष्सेफ हेवनष परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। अमेरिकी डॉलर, सोना और विकसित देशों के सरकारी बॉन्ड ऐसे समय में अधिक आकर्षक बन जाते हैं।इसके विपरीत उभरते बाजारों में निवेश अपेक्षाकृतजोखिमपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि जून के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से भारी विदेशी पूंजी निकासी देखने को मिली साथियों एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार का ऊंचा मूल्यांकन और मुनाफावसूली है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, कॉर्पोरेट आय में वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारतीय बाजारों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई। अनेक प्रमुख सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों ने अपने निवेश पर लाभ सुरक्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली की। वैश्विक फंड प्रबंधक अक्सर उन बाजारों में लाभ बुक करते हैं जहां उन्हें लगता है कि मूल्यांकन काफी ऊंचा हो चुका है और आगे की वृद्धि सीमित हो सकती है। भारतीय बाजार में हालिया बिकवाली को इसी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।इसके अतिरिक्त भारतीय रुपये की कमजोरी भी विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय रही है। यदि कोई विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में लाभ कमाता है लेकिन उसी अवधि में रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले घट जाता है, तो वास्तविक डॉलर आधारित रिटर्न कम हो जाता है। यही कारण है कि मुद्रा जोखिम भी विदेशी निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करता है। 2026 में रुपये की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों की चिंता को और बढ़ाया है। साथियों एनएसडीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2026 में फरवरी को छोड़कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हर महीने भारतीय शेयरों के शुद्ध विक्रेता रहे हैं। जनवरी में उन्होंने लगभग 35,962 करोड़ रूपए की निकासी की।फरवरी में स्थिति थोड़ी सुधरी और लगभग 22,615 करोड़ रूपए का निवेश आया, जो 17 महीनों में सबसे बड़ा मासिक प्रवाह था। लेकिन मार्च में रिकॉर्ड 1. 17 लाख करोड़ रूपए की बिकवाली हुई। अप्रैल में 60,847 करोड़ रूपए और मई में 32,963 करोड़ रूपए की निकासी दर्ज की गई। जून के पहले पंद्रह दिनों में ही 62,853 करोड़ रूपए की बिकवाली हो चुकी है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में कुल विदेशी निकासी लगभग 2.87 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गई है, जो पूरे वर्ष 2025 की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ से भी कहीं अधिक है। यह आंकड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाए गए हैं। साथियों यह आंकड़े दर्शाते हैं कि विदेशी निवेशकों का रुख केवल अल्पकालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक रणनीतिक पुनर्संतुलन का हिस्सा है। हाल के महीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंपनियों और अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित हुआ है। अनेक वैश्विक फंड उभरते बाजारों से धन निकालकर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और एआई से संबंधित अवसरों में निवेश कर रहे हैं। इससे भारत सहित कई देशों के शेयर बाजारों पर दबाव बना

है।हालांकि विदेशी निवेशकों की इस लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से धराशायी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में म्यूचुअल फंड निवेश, व्यवस्थित निवेश योजना, पेंशन फंड और बीमा कंपनियों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों द्वारा बेचे जा रहे शेयरों को बड़े पैमाने पर खरीदा है। यही कारण है कि बाजार में अस्थिरता तो बढ़ी है, लेकिन व्यापक गिरावट नहीं आई। भारतीय पूंजी बाजार की यह संरचनात्मक मजबूती पिछले दशक की तुलना में कहीं अधिक सशक्त दिखाई देती है। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह स्थिति एक महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। पहले विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सीधा प्रभाव बाजार पर गंभीर रूप से पड़ता था, लेकिन अब घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर आ रहा है। इससे भारतीय बाजारों की विदेशी पूंजी पर निर्भरता धीरे–धीरे कम हो रही है। हालांकि विदेशी निवेश अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन घरेलू निवेशकों की बढ़ती भूमिका बाजार को स्थिरता प्रदान कर रही है।आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी पूंजी का निरंतर बहिर्वाह चालू खाते के घाटे, रुपये की विनिमय दर और पूंजी बाजार की तरलता पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक और नीति निर्माता विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रहे हैं। हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बॉन्ड बाजार में पहुंच बढ़ाने और विदेशी निवेश नियमों को सरल बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि वैश्विक निवेशकों का विश्वास बना रहे। साथियों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की दृष्टि से आने वाले सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अमेरिका–ईरान वार्ता का परिणाम, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति, जापान के केंद्रीय बैंक के निर्णय और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के संकेतक पूंजी प्रवाह की दिशा तय करेंगे। यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है और तेल कीमतों में स्थिरता आती है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह सकारात्मक होगा। वहीं यदि संघर्ष बढ़ता है तो ऊर्जा लागत, मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश प्रवाह पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जून 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई 62,853 करोड़ रूपए की भारी बिकवाली केवल भारतीय शेयर बाजार की घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में चल रहे व्यापक बदलावों का प्रतिबिंब है।अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, ऊंची बॉन्ड यील्ड, पश्चिम एशिया का भू–राजनीतिक तनाव, रुपये की कमजोरी, एआई आधारित निवेश अवसरों की ओर वैश्विक पूंजी का झुकाव और भारतीय बाजारों में मुनाफावसूली,इन सभी कारकों ने मिलकर विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार से धन निकालने के लिए प्रेरित किया है।फिर भी घरेलूनिवेशकों की बढ़ती ताकत और भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विकास क्षमता यह संकेत देती है कि यह चुनौती अस्थायी हो सकती है। आने वाले समय में यदि वैश्विक तनाव कम होता है और निवेशकों का जोखिम लेने का विश्वास लौटता है, तो भारत पुनः विदेशी पूंजी का प्रमुख गंतव्य बन सकता है। फिलहाल यह दौर भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती, घरेलू निवेशकों के विश्वास और आर्थिक लचीलेपन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए।

सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव पर सक्रिय केंद्र सरकार

–अतिवीर जैन

पांच राज्यों के चुनाव से निवृत्त होकर गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर ध्यान दिया और इस हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई। उल्लेखनीय है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के अध्ययन हेतु 26 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने समिति गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट एक साल में केंद्र सरकार को सौंपेगी। यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश से बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम आदि में घुसपैठ कराने वाले तत्व संगठित रूप से काम कर रहे हैं। तभी उनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट भी बन जाते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमावर्ती जिलों से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं और स्थानीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव कर रहे हैं। जहाँ बांग्लादेश से सामूहिक घुसपैठ होती है, वहीं चीन सीमा और नेपाल की सीमा से इन घुसपैठियों के लिए काम करने वाले पैसे वाले और प्रभावशाली विदेशी माफियाओं, अराजक तत्वों की घुसपैठ होती है, जिन्हें हमारे यहाँ कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल जाता है। ये ही लोग इन घुसपैठियों को पूरे देश में सामूहिक श्रमिकों के रूप में महानगरों में फैलाते और बसाते हैं।अपनी सेवा के दौरान बेंगडुब्बी में पोस्टिंग के समय मैंने सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, बिनागुड़ी आदि क्षेत्रों की सड़क मार्ग से यात्रा की थी। इसमें मैंने बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगे इन क्षेत्रों को देखा था। नेपाल से तो भारतीयों और नेपालियों का आना–जाना ऐसे ही है जैसे भारत के एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना। वहाँ बाजार में नेपाली मुद्रा और भारतीय मुद्रा दोनों समान रूप से चलती हैं। वहीं बांग्लादेश की सीमा पर कुछ क्षेत्रों में तार लगे हुए थे और हमारे बीएसएफ के सैनिक भी तैनात थे। भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच कहीं नदियाँ, कहीं गड्ढे और कहीं छोटी–छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई थीं। वहीं अधिकांश भाग में न तो काँटेदार तार लगे हुए थे और न ही कोई सैनिक तैनात थे। ऐसे क्षेत्रों से ज्यादातर बांग्लादेशियों का आना–जाना सामान्य बात थी। बांग्लादेशी प्रतिदिन प्रयोग होने वाली सामग्री, यथा बर्तन, साइकिल, साबुन, दाल–मसाले आदि भारत से लेकर जाते थे और बांग्लादेश में दोगुने से भी अधिक मूल्य पर बेच देते थे। पशुओं का भी आदान–प्रदान किया जाता था। भारतीय सामान ज्यादातर नावों और तख्तों के सहारे बांग्लादेश में ले जाया जाता था। भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम 1986 से चल रहा था।

राशिफल

मेष :– भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख–दुख के प्रति चितित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्मक विचार ला सकती हैं।

वृषभ :– भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।

मिथुन :– भावनाओं पर नियंत्रणवश अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक–सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह :– किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कतई न करें।

कन्या :– नये संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुला :– कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन–सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक :– किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु :– रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।

मकर :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन–सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा–पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन :– पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

मेदांता लखनऊ में 400वां किडनी ट्रांसप्लांट सफल, मरीज को मिली नई जिंदगी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। किडनी की गंभीर बीमारी से परेशान एक मरीज जब मेदांता लखनऊ पहुंचा, तब उसकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। मरीज लंबे समय से इलाज करा रहा था और नियमित डायलिसिस पर निर्भर था। बीमारी की वजह से उसका सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा था। मेदांता के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीज की पूरी जांच की और पाया कि उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर विकल्प है। परिवार की सहमति और सभी जरूरी प्रक्रियाओं के बाद मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। खास बात यह रही कि यह मेदांता लखनऊ का 400वां किडनी ट्रांसप्लांट था, जिसने अस्पताल के ट्रांसप्लांट कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को जोड़ा। 25 जून 2020 को शुरू हुए मेदांता लखनऊ के किडनी ट्रांसप्लांट कार्यक्रम ने आज सैकड़ों मरीजों को नया जीवन देने का काम किया है। कोविड–19 महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच शुरू हुए इस कार्यक्रम ने लगातार प्रगति की और जून 2026 तक 419 सफल किडनी ट्रांसप्लांट पूरे कर लिए। अस्पताल में 57 इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक तकनीक की मदद से किए गए ट्रांसप्लांट और कई हाई रिस्क मामलों में भी अच्छे नतीजे मिले हैं। अस्पताल ने 9 वर्ष की आयु के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के मरीजों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। वहीं 76 वर्ष तक की आयु के अंगदाताओं ने भी अपने प्रियजनों को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेदांता लखनऊ में अब तक सबसे अधिक अंगदान परिवार के सदस्यों ने किया है। 139 पत्नियों, 130 माताओं और दादी, 42 बहन और भाभी सहित बड़ी संख्या में परिजनों ने अपने प्रियजनों के लिए किडनी दान की है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य पिता, भाई, बेटियां और पति भी अंगदाता बने हैं। यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा क्षेत्र की सफलता है, बल्कि परिवारों के प्रेम, त्याग और भरोसे की भी कहानी है। डॉ. राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर एवं डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी ने कहा, 400वां किडनी ट्रांसप्लांट हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के भरोसे का

प्रतीक है। हर सफल ट्रांसप्लांट किसी व्यक्ति को नया जीवन और उसके परिवार को नई उम्मीद देता है। हमारी टीम का लक्ष्य हमेशा सुरक्षित और बेहतर इलाज देना रहा है। हमें खुशी है कि हम मुश्किल मामलों में भी लगातार अच्छे नतीजे दे पा रहे हैं। डॉ. राज कुमार शर्मा, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी ने कहा, ष्किडनी फेल होने वाले कई मरीज लंबे समय तक डायलिसिस पर निर्भर रहते हैं। सही समय पर किया गया किडनी ट्रांसप्लांट उन्हें बेहतर और सामान्य जीवन जीने का मौका देता है। 400 से अधिक सफल ट्रांसप्लांट इस बात का प्रमाण हैं कि अनुभवी टीम, एडवांस्ड तकनीक और मरीजों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। हम लोगों से अंगदान के प्रति जागरूक होने की भी अपील करते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता में डॉ. अनीश श्रीवास्तव, डायरेक्टर यूरोलॉजी रोबोटिक्स एंड किडनी ट्रांसप्लांट, डॉ. धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी, डॉ. मनमीत सिंह, डायरेक्टर – यूरोलॉजी रोबोटिक्स एंड किडनी ट्रांसप्लांट, डॉ. रोहित कपूर, सीनियर कंसल्टेंट – यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एवं किडनी ट्रांसप्लांट, डॉ. इमरान अहमद खान, सीनियर कंसल्टेंट – यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एवं किडनी ट्रांसप्लांट, डॉ. मनीष खट्टर, कंसल्टेंट – यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एवं किडनी ट्रांसप्लांट तथा डॉ. नवनीत सौरव, एसोसिएट कंसल्टेंट – यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एवं किडनी ट्रांसप्लांट सहित नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, नर्सिंग, रेडियोलॉजी और लैब की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेदांता लखनऊ का किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। अस्पताल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद मरीजों तक आधुनिक ट्रांसप्लांट सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि उन्हें स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने का मौका मिल सके।

इग्नू ने शुरू किया एम.एससी. इन क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम, 15 जुलाई तक होंगे प्रवेश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र से दो वर्षीय एम.एससी. इन क्लाइमेट चेंज (M.Sc. in Climate Change) कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है तथा इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यह अभिनव स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया है। पाठ्यक्रम में क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट रिस्क, अनुकूलन एवं शमन, जल संसाधन, कृषि आपदा, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण कानून, पर्यावरणीय प्रशासन तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज की अवधारणाओं को भी समाहित किया गया है। इग्नू इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनामिका सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि चार वर्ष निर्धारित की गई है। यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होगा तथा कुल 80 क्रेडिट का होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष के 40 क्रेडिट सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लाइमेट चेंज प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं अथवा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, सेक्टर–5, वृंदावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

समर वेकेशन खत्म, राजधानी के स्कूलों में लौटी रौनक, छात्रों को तिलक लगाकर स्वागतय

संवाददाता

लखनऊ। 27 दिन के समर वेकेशन के बाद आज मंगलवार से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फिर से रौनक लौट आई। स्कूल पहुंचने पर तिलक लगाकर स्टूडेंट्स का स्वागत किया

गया। कुछ जगह आरती भी उतारी गई और गिफ्ट देकर उनका वेलकम किया गया। पहले दिन विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति सामान्य दिनों की तुलना में कुछ कम रही, लेकिन जो बच्चे पहुंचे उनका जोरदार स्वागत हुआ। छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे सहपाठियों और शिक्षकों से मिलकर काफी खुश नजर आए। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय खुलने के पहले दिन को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की गई थी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालय पहुंचने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों का आत्मीय स्वागत करें और सकारात्मक और उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण करने को कहा गया था। लंबे अवकाश के बाद विद्यालय लौट रहे बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि वे पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई में पुनः जुड़ सकें। पहले दिन प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों को नई कक्षा, पाठ्यक्रम और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी देने के निर्देश जारी किए गए थे। विद्यालय खुलने के साथ ही नियमित शिक्षण कार्य, खेलकूद गतिविधियां, पुस्तकालय संचालन, मिड डे मील योजना और अन्य सह–शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए। विभाग ने सभी विद्यालयों को साफ–सफाई, नामांकन सत्यापन, छात्र उपस्थिति और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्र–छात्राओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालयों में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। छात्राओं और दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास के साथ ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

संक्षिप्त

बीजेपी के हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण के पीछे बड़ा घोटाला, न्यायिक जांच हो : अखिलेश यादव

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजनाओं में घपले–घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार को बहुसदस्यीय न्यायिक जांच की मांग की। सपा प्रमुख ने यह मांग राम मंदिर के दान पात्र और वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच शुरू होने के बाद उठाई है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा सरकार के बनाए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे जो घपला–घोटाला है, उसकी बहुसदस्यीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, इसमें संलिप्त किसी ट्रस्टी, किसी समिति के सदस्य या किसी प्रशासनिक एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतने बड़े घोटाले इन सभी की मिलीभगत से ही संभव होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में इन परियोजनाओं से जुड़े रहे सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों तथा इनमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों की कथित रूप से अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों और अकूत धन–संपदा की भी जांच होनी चाहिए। यह जांच आम जनता, ईमानदार पत्रकारों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की निगरानी में कराई जानी चाहिए।

फीस वृध्दि के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को मिला सपा समर्थित अंबेडकर वाहिनी का साथ, भाजपा सरकार पर बोला हमला

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं के विरोध में पिछले 15 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन

ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने समर्थकों के साथ धरनास्थल पहुंचकर निष्कासित छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ–साथ भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र प्रेम प्रकाश यादव, शशि प्रकाश प्रिंस और हर्षित शुक्ला को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्कासित किए जाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए भारती ने इसे छात्र आवाज को दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को संवाद के बजाय दंडित किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। मिठाई लाल भारती ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में छात्र, युवा, किसान, मजदूर और व्यापारी सभी वर्ग उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अंबेडकर वाहिनी ने चेतावनी दी कि यदि निष्कासित छात्रों की बहाली नहीं हुई और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाया जाएगा। यह जानकारी सपा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू भारती सुदर्शन दी। धरने में अवनीश यादव, प्रिंस कुमार, सत्येंद्र कुमार पानू समेत बड़ी संख्या में छात्र नेता और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

फरवरी से आज तक नहीं खुल पा रही आरटीई की वेब-साइट

नियमों को दर–किनार कर बेसिक शिक्षा विभाग भेज रहा आरटीई के अपात्र एडमिशन

संवाददाता

लखनऊ। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमों को किनारे कर निजी विद्यालयों में जबरन प्रवेश लेने का दबाब बना रहा है। लाभार्थी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की आरटीई लिस्ट तथा स्टूढेप्ट स्टेटस का खुलना जरूरी है। इसी से चयनित बच्चे की सत्यता पता चलती है। विभाग की वेब–साइट इस बार जबसे आदटीई प्रवेश की प्रक्रिया आरम्भ हुयी है तब से आज तक नहीं खुली है, और विभाग ने भी इस दिशा में आज तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग अपना पल्ला एनआईसी पर झाड़ रहा है कि वेब–साइट को ठीक करना एनआईसी का काम है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों से परे आरटीई के एडमिशन निजी विद्यालयों में भेज रहे है साथ ही फोन कर जबरन प्रवेश लेने को कहते है। आरटीई एडमिशन के नियमानुसार पहले से कियी निजी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चें का आरटीई के तहत प्रवेश नहीं हो सकता है। परन्तु विभाग की मेहरबानी सं बच्चा जिस निजी विद्यालय में पहले से पढ़ रहा है उसी निजी विद्यालय में बच्चें को आरटीई में प्रवेश लेने के जिए भेज दिया। साथ ही फोन कर बच्चे का प्रवेश लेने का दबाब भी बना रहे है। विभागीय भ्रष्टाचार के चलते अपात्रों के अभिभावक प्रतिदिन विद्यालय आकर प्रवेश लेने के लिए दबाब बनाते है तथा झगड़ा भी करते है। शिक्षा का अधिकार के लहत अलाभित समूह तथा दुर्बल आय वर्ब के बच्चे को आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है। नियमानुसार ऐसे अभिभावकों के पास बीपीएल राशन राशन कार्ड होना चाहिए। जो सामान्यतः किसी के पास नहीं होता है। परंतु 60,000 या 80,000 रूपये वार्षिक आय का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के ये दुर्बल आय वर्ग के बन कर आरटीई के तहत आवेदन कर देते है। और विभाग न तो आय प्रमाण या निवास प्रमाण पत्र की कोई जांच करता है। बस लाटरी में नाम निकाल कर निजी स्कूलों में भेज देता है।

आस्था स्थलों के विकास को योगी सरकार ने दी रफ्तार, 8 जिलों की 33 परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम

79 करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च, पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर टेंपल इकोनॉमी की जाएगी मजबूत `आस्था के साथ विकास' प्रदेश सरकार की प्राथमिकता : मंत्री जयवीर सिंह

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रदेश के 8 जिलों में 33 पर्यटन एवं धार्मिक विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है, जिन पर लगभग 79. 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता 'आस्था के साथ विकास' है। इसी सोच के तहत धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का सौंदर्यीकरण कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर टेंपल इकोनॉमी को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है और कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को 8 जिलों की 33 परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 79.17 करोड़ रुपये से अधिक है।

आधुनिक सुविधाओं से जुड़ेंगे आस्था स्थल

इन परियोजनाओं में लखनऊ और सीतापुर की एक–एक परियोजना, मिर्जापुर की 7, भदोही की 5, सोनभद्र की 2, हमीरपुर की 2, महोबा की 3, बांदा और चित्रकूट की 6–6 परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के विभिन्न आस्था स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई दी जाए।

परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि का ब्योरा

जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ स्थित मोहनलाल गंज में हुलासखेड़ा का पर्यटन विकास के लिए 11.99 करोड़, सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में बेदारण्यम की स्थापना कार्य के लिए 1.49 करोड़ रुपये, मिर्जापुर की 07 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1. 04 करोड़, करोड़, 79.64 लाख, 1. 94 करोड़, 1.97 करोड़, 83.69 लाख, 88.87 लाख और 2.15 करोड़ रुपये के करीब धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भदोही जनपद की 05 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1. 03 करोड़, 1.47 करोड़, 1.45 करोड़ 99.97 लाख, 1.25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं सोनभद्र जनपद की 02 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1.25 करोड़ और 1. 16 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसी तरह महोबा जनपद के विभिन्न मंदिरों के लिए क्रमशः 1.08 करोड़ रुपये, 45. 58 लाख और 71.77 लाख रुपये तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए। हमीरपुर की 02 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 70 लाख और 69.81 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। बांदा की 06 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 53.82 लाख, 1.38 करोड़, 1.14 करोड़, 1.30 करोड़, 3.38 करोड़ और 2.83 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। वहीं चित्रकूट की 06 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1.81 करोड़, 2.29 करोड़, 5.25 करोड़, 1. 71 करोड़, 1.66 करोड़ और 9.05 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

निविदा की कार्यवाही भी जारी

उन्होंने बताया कि लगभग सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने के लिए निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सेक्टर की लोकप्रियता एवं निवेश की असीमित संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार आस्था के साथ विकास के अंतर्गत सभी स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं सुलभ करा रही है।

आप सबका साथ रहा तो इंदौर को पीछे छोड़ेगा लखनऊ : सुरेश खन्ना

पीएम मोदी की वजह से हमारी प्राथमिकताएं दुनिया ने स्वीकारीं

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को नैमिषारण्य भवन में मोदी सरकार के 12 साल के काम गिनाए। इस दौरान उन्होंने कहा गांधीजी के बाद अगर किसी ने सही मायने में स्वच्छता पर काम किया तो वह पीएम मोदी हैं। स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ तीसरे नंबर पर आया था। आप सभी का सहयोग रहा तो इस बार लखनऊ सफाई में इंदौर को पीछे छोड़ देगा। पीएम मोदी ने पूरी कमबैक प्लानिंग के साथ काम किया और इंट्रोड्यूस किया। हर तरह से इसको सफल बनाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे देश में स्वच्छता का एक माहौल बना है। स्वच्छता अभियान से हमारी दिनचर्या पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इसे दुनिया भी अपना रही है। पीएम मोदी की वजह से हमारी प्राथमिकताएं दुनिया ने स्वीकारी हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी है। जिस समय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसके कुछ ही

दिनों बाद छात्रों के लिए बहुत बड़ा फैसला किया था। उससे पूरा देश प्रभावित हुआ और उन्होंने खुशी जाहिर की बच्चों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को पहले अटेस्ट कराना पड़ता था। उन्होंने उसको सेल्फ अटेस्टेशन किया जो सभी छात्रों के लिए फायदेमंद रहा। योग को पतंजलि ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। उसको प्रधानमंत्रीजी ने पूरी दुनिया के सामने 11 दिसंबर 2014 को दुनिया के सामने रखा और 175 देश के बहुमत से इसको पारित किया गया और आज पूरी दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को हम मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग से लेकर फसल बीमा योजना तक नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने विशेष रूप से फोकस करके कोशिश की थी कि हमारे किसानों की उपज बढ़े। हमारे अन्नदाता वर्ग को सबसे ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया है और आज हमारे देश में उत्पादन किया बहुत बड़ी मात्रा पड़ी है। उसका संपूर्ण श्रेय हमारे देश के किसानों को और प्रधानमंत्रीजी और पूरी कैबिनेट को जाता है। सॉइल टेस्टिंग बड़े पैमाने पर उन्होंने कार्ड बताकर किया साथ ही साथ लिंक पोटेंट यूरिया का जो पहले व्यवस्था नहीं थी उसको किया इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को कम ब्याज पर लोन लेने की व्यवस्था बनाई ताकि लोग फसल के संबंध में लोन लेकर अपना काम चल सके और अपने उत्पादकता को बढ़ासकें। और किसान सम्मन निधि के रूप में पूरे देश के 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है और छोटे किसानों को 6000 सालाना की व्यवस्था की एक तरफ जमीन की टेस्टिंग की गई और दूसरी तरफ फसल बीमा योजना के माध्यम से तो को काम किया और मुनाफा बढ़ाया। इस प्रकार 78 करोड़ 41 लाख ऐसे किसान हैं जो लगातार 2016 के बाद से अब तक लाभान्वित हुए हैं। उन्हें 1.83 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। साथ ही लगातार हर वर्ष जितनी भी फसलें थीं, उनकी एमएसपी कभी 50:, कभी 60:, कभी 70:, कभी 100: बढ़ाकर उन्होंने किसानों को यह कोशिश की कि वह हर तरह से किसान संपन्न हो। अगर वह संपन्न होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। मनरेगा योजना जो बहुत पुरानी योजना थी जिसमें 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दिया, जो कि 1 जुलाई 2026 से वीबी–जीरामजी के नाम से लागू होने जा रही है। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि, हम जानते हैं कि रासायनिक खाद्य हमारे जमीन के उर्वरक को खत्म करते हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती की तरफ प्रसारित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 में 3.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 1,198 एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे।

ट्रेन में सीट नहीं मिली तो बोला-बम है, गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस में मची अफरा-तफरी

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर–तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस के रुकते ही उसमें से सभी यात्री उतरकर भागने लगे। तुरंत आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वॉड की टीमें ट्रेन के अंदर दाखिल हुईं। कई कोच में जा–जाकर जांच की। मंगलवार को यह घटना इसलिए हुई क्योंकि ट्रेन के अंदर एक युवक ने सीट न मिलने पर अफवाह उड़ा दी थी कि इसमें बम है। उसकी अफवाह के चलते ट्रेन को ऐशबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म–1 पर रोक दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। करीब आधे घंटे की सघन तलाशी के दौरान ट्रेन में कुछ नहीं मिला तो जीआरपी ने यात्रियों से पूछना शुरू किया कि किसने यह सूचना दी। इस पर लोगों ने एक युवक की तरफ इशारा किया। युवक को हिरासत में ले लिया गया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।

रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे पूरे अभियान की निगरानी की। अधिकारियों के अनुसार, बम की सूचना की सत्यता की जांच की गई। किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। थाना बाजारखाला पुलिस के अनुसार, अफवाह फैलाने वाले युवक ने अपना नाम–पता तेलंगाना के विमलवाड़ा रजाना का रहने वाला सैनी जैकी बताया। स्थानीय पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान ट्रेन और उसके सभी कोचों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई। बम मिलने की सूचना पूरी तरह से झूठी थी। जांच के बाद ट्रेन को सुरक्षित पाए जाने पर उसे अपने अगले गंतव्य के लिए सकुशल रवाना कर दिया गया। अफवाह फैलाने वाले युवक ने बताया है कि ट्रेन में बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिल रही थी। इसी कारण उसने ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना फैला दी, जिससे यात्रियों के बीच अफरा–तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जीआरपी ने उसे हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

ऊँ कल्याणम द्वारा "यंग तपस्वी" कार्यक्रम आयोजित, बच्चों और युवाओं के समग्र कल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी पहल

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन से राष्ट्र निर्माण की दिशा में कल्याणम वेलनेस की अनूठी पहल

बीएनई

देहरादून। मिसरा पट्टी कल्याणम वेलनेस सेंटर देहरादून में यंग तपस्वी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों और युवाओं के समग्र कल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी पहल रही। वर्तमान समय अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर है। तकनीकी क्रांति, डिजिटल जीवनशैली और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने जहां जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं नई पीढ़ी विशेषकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक व्यवहार और आंतरिक संतुलन के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आज का बच्चा ज्ञान तो अर्जित कर रहा है, लेकिन जीवन को समझने की कला, आत्मसंवाद, संवेदनशीलता, अनुशासन और आत्मिक चेतना जैसे मूल तत्व धीरे–धीरे कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं, बल्कि आवश्यकता एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण की है जो बाल मन, शरीर, व्यवहार और चेतन चारों स्तरों पर विकास सुनिश्चित करे। इसी व्यापक चिंतन और मानव कल्याण की भावना के साथ ध कल्याणम द्वारा संचालित "यंग तपस्वी" कार्यक्रम आज बच्चों और युवाओं के होलिस्टिक वेलनेस अर्थात समग्र कल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी पहल के रूप में स्थापित हो रहा है। यह कार्यक्रम केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आंतरिक ऊर्जा जागरण और संतुलित जीवनशैली विकसित करने की एक जीवन यात्रा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिन त्यागी ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को ऐसे आयोजनों की सबसे अधिक आवश्यकता है, जो बच्चों को केवल अकादमिक रूप से सक्षम न बनाएं, बल्कि उन्हें जीवन के हर आयाम में संतुलित और सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि यंग तपस्वी का उद्देश्य बच्चों के भीतर सोशल स्किल, फिजिकल फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को जानकारी तो दे रही है, लेकिन जीवन जीने की कला, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति जैसे विषयों पर गंभीर प्रयास कम दिखाई देते हैं। ऐसे में कल्याणम का प्रयास है कि नई पीढ़ी को जीवन के वास्तविक मूल्यों, संतुलित सोच और स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ा जाए। सचिन त्यागी ने कहा कि कल्याणम का मूल दर्शन "व्यक्ति का आंतरिक विकास ही समाज और राष्ट्र के स्थायी विकास की आधारशिला है।" संस्था का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसी

पीढ़ी तैयार करना है जो मानसिक रूप से सजग, शारीरिक रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से संवेदनशील और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। उनका कहना है कि जब बच्चे भीतर से मजबूत बनेंगे तभी समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। यही सोच संस्था के हर प्रयास की आधारशिला है। वहीं राहुल सिंह पंवार ने बताया कि यंग तपस्वी अब एक राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस विशेष कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से बच्चे शामिल हुए हैं, जबकि उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए देश के अलग–अलग क्षेत्रों से अनुभवी ट्रेनर्स पहुंचे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आज देशभर में अभिभावक और युवा ऐसी पहल की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जो बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर जीवन के व्यापक आयामों से जोड़ सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनकी आंतरिक क्षमता से परिचित कराना, आत्मविश्वास विकसित करना, नेतृत्व क्षमता को जागृत करना, सामूहिक सहयोग की भावना विकसित करना और उन्हें जीवन के प्रति सजग एवं संतुलित दृष्टिकोण देना है। यंग तपस्वी बच्चों को केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि भीतर से मजबूत, शांत और जागरूक व्यक्तित्व बनने की दिशा में तैयार करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को योग, ध्यान, शारीरिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, सामूहिक नेतृत्व, संवाद कला, आत्मअनुशासन, भावनात्मक प्रबंधन और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों के भीतर सुप्त ऊर्जा को जागृत करना और उन्हें स्वस्थ, संतुलित तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करना रहा। आयोजकों का मानना है कि भारत का भविष्य केवल आर्थिक या तकनीकी विकास से सशक्त नहीं होगा, बल्कि तब सशक्त होगा जब देश की नई पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों, आत्मिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होगी। आज आवश्यकता केवल सफल व्यक्तियों की नहीं बल्कि संतुलित, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों की है। कल्याणम इसी विचारधारा के साथ कार्य कर रहा है कि आने वाला भारत केवल विकसित नहीं बल्कि भीतर से स्वस्थ, संतुलित और चेतनाशील भारत बने। यंग तपस्वी उसी संकल्प की एक जीवंत अभिव्यक्ति है, जो नई पीढ़ी को स्वयं से जोड़ते हुए समाज और राष्ट्र के व्यापक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह आयोजन एक कार्यक्रम भर नहीं, बल्कि उस परिवर्तनकारी विचार का प्रारंभ है जो आने वाले समय में भारत के युवाओं और बच्चों को एक नई दिशा, नई चेतना और एक संतुलित जीवन दृष्टि प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने एसपीएस कंस्ट्रक्शंस द्वारा निर्माणाधीन शिमला बाईपास परियोजना की प्रगति का किया अवलोकन

बीएनई

शिमला। देश की अग्रणी अवसंरचना निर्माण कंपनियों में से एक एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एसपीएस कंस्ट्रक्शंस) ने प्रतिष्ठित चार–लेन शिमला बाईपास परियोजना (पैकेज–1 – कैथलीघाट–शकराल) के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला दौरे के दौरान परियोजना की प्रगति की समीक्षा की तथा निर्माण कार्यों और प्रमुख उपलब्धियों का निरीक्षण किया। इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रही एसपीएस कंस्ट्रक्शंस चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग में जटिल राजमार्ग और सुरंग निर्माण कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रही है। कंपनी ने प्रमुख सुरंग खंडों में सफल आर–पार खुदाई (ब्रेकथ्रू) सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिससे देशभर में तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की उसकी क्षमता और विशेषज्ञता और मजबूत हुई है। परियोजना की प्रगति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एसपीएस कंस्ट्रक्शंस के निदेशक रोहित सिंगला ने कहा, हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। पर्वतीय क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण उच्च स्तर की इंजीनियरिंग सटीकता, मजबूत योजना और समर्पित कार्यबल की मांग करता है। परियोजना के विभिन्न

महत्वपूर्ण हिस्सों में हासिल की गई प्रगति हमारी टीमों की दक्षता और उत्कृष्ट निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध निष्पादन के सर्वोच्च मानकों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। शिमला बाईपास परियोजना से शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या को कम करने, यात्रा को अधिक सुगम और तेज बनाने तथा पूरे हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। परियोजना के पूर्ण होने पर यह संपर्क मार्ग स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और वाणिज्यिक परिवहन के लिए आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाएगा तथा क्षेत्र के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा।

भाटापारा में गौरव का दिन : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया छत्तीसगढ़ महतारी और शहीद खोण्डे की प्रतिमा का अनावरण

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के अपने एक दिवसीय प्रवास पर भाटापारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर को एक बड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक

सौगात देते हुए छत्तीसगढ़ महतारी और देश के वीर सपूत शहीद श्रीकृष्ण गजानन खोण्डे की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। शहीद को नमन करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शहीद श्रीकृष्ण गजानन खोण्डे की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों और युवाओं के लिए राष्ट्रसेवा की प्रेरणा बनेगी। देश उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस गरिमामय समारोह में राज्य के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस संवेदनशील अवसर पर विधानसभाध्यक्ष डॉ. सिंह ने शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के परिजनों (पुत्री प्रिया खोण्डे और भाई प्रभाकर खोण्डे) से बेहद आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना।

छत्तीसगढ़ महतारी चौक पर नमन

अपने प्रवास के दौरान डॉ. रमन सिंह सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी चौक पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पारंपरिक विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर राज्य की सुख–समृद्धि की कामना की।

1971 के युद्ध के नायक शहीद खोण्डे को दी श्रद्धांजलि

इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष भाटापारा स्थित शहीद श्रीकृष्ण गजानन खोण्डे परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने वर्ष 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद श्रीकृष्ण गजानन खोण्डे की प्रतिमा का अनावरण किया।

समारोह में कई दिग्गज रहे मौजूद

इस ऐतिहासिक गरिमामय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा और डॉ. सनम जांगड़े उपस्थित थे। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, जनप्रतिनिधिगणों के साथ–साथ बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा और भारी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।

लोकभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए AI प्रशिक्षण सत्र आयोजित

बीएनई

रायपुर। लोकभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने तथा शासकीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Artificial Intelligence (AI) संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन अवर सचिव अनुभव शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को AI (Artificial Intelligence) की कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावी इस्तेमाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। सत्र में AI के माध्यम से कार्यों को अधिक सरल, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक तकनीक की उपयोगी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यप्रणाली में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों– कर्मचारियों को डिजिटल दक्षताओं से सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार सत्यभामा अजय दुबे, उप सचिव निधि साहू, सुधीर सुलतानिया, लक्षित त्रिलोक सेठिया, अनूप अग्रवाल एवं लोकभवन के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

जी7 में ट्रंप ने उड़ाई इजराइल की धज्जियां, नेतन्याहू को लगाई फटकार, बोले–दोस्ती अपनी जगह, लेकिन...

एजेंसी

मास्को। फ्रांस में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप ने जी7 शिखर सम्मेलन के मंच से अपने सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले इजराइल की जमकर धज्जियां उड़ाईं और नेतन्याहू को सार्वजनिक मंच पर खरी–खोटी सुना डाली। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को लेबनान के मुद्दे पर अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह लेबनान में इजरायल की कुछ सैन्य कार्रवाइयों से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते की घोषणा से कुछ घंटे पहले बेरूत पर इजरायली हमले उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, मैंने इजरायल को यह बात बता भी दी थी। मुझे वह हमला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अब तक नेतन्याहू सरकार का सबसे मजबूत समर्थक माना जाता रहा है।लेबनान में भ्रइवससी के खिलाफ जारी सैन्य अभियान पर ट्रंप ने कहा कि बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी एक व्यक्ति की तलाश में हर बार पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन इमारतों में रहने वाले सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल को सुझाव दिया था कि लेबनान में हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। उनके अनुसार, मुझे लगता है कि सीरिया यह काम बेहतर तरीके से कर सकता है। उधर, ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि लेबनान पर कोई नया इजरायली हमला या वहां कब्जा बनाए रखना अमेरिका–ईरान अंतरिम समझौते का उल्लंघन माना जाएगा।

टाटा मोटर्स पीवी को चालू वित्त वर्ष में उद्योग में सबसे तेज वृध्दि की उम्मीद : चंद्रशेखरन

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को व्यापक

आर्थिक एवं वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2026–27 में उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने का भरोसा है। चंद्रशेखरन ने कंपनी की 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) और उसकी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। इससे दक्षता बढ़ेगी, सीखने की गति तेज होगी और पूंजी अनुशासन मजबूत होगा। उन्होंने कहा, हम वित्त वर्ष 2026–27 में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जो नए उत्पादोंऔर बहु–पावरट्रेन पेशकशों से समर्थित है। हमारा ध्यान उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने, सुरक्षा, स्थिरता, गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करने पर रहेगा। साथ ही व्यापक आर्थिक और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बने रहने पर जोर देंगे। समूह की कंपनियों के बीच तालमेल पर उन्होंने कहा कि टीएमपीवी और जेएलआर विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन में सहयोग जारी रखेंगे जिससे दक्षता बढ़ेगी, सीखने की गति तेज होगी और पूंजी अनुशासन मजबूत होगा। चंद्रशेखरन ने साथ ही कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआई) में वैश्विक स्तर पर तेज प्रगति से परिवहन उत्पादों के डिजाइन, अनुभव और समर्थन के तरीके बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, इसी के साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, सुरक्षा को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन प्रतिस्पर्धा को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। भू–राजनीतिक स्थितियां तथा असमान आर्थिक सुधार से और जटिलता बढ़ रही है, जिससे लचीलापन एवं मजबूती बेहद महत्वपूर्ण क्षमताएं बन गई हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में कंपनी ने 92,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचे, जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 43.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

सरकार के 12 वर्ष कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 2025-26 में 49%

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014–15 के 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025–26 में 48.8 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि आईटी क्षेत्र के तेज विस्तार, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) में बढ़ोतरी और वैश्विक महामारी के बाद सेवाओं की डिजिटल आपूर्ति की ओर बदलाव के कारण हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सेवा निर्यात 2014–15 के 158.1 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 421.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक, देश का कुल निर्यात (वस्तु व सेवाएं मिलाकर) 2014–15 के 468 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 863 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवा निर्यात में पिछले 12 वर्षों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। केवल 2020–21 में कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण इस पर असर पड़ा। कुल

सेवा निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रमुख वृद्धि चालक बनी हुई हैं। पेशेवर एवं प्रबंधन परामर्श दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा। मंत्रालय ने कहा, पिछले 12 वर्षों में सेवा निर्यात में 9.3 प्रतिशत की वार्षिक दर दर्ज की गई है। वस्तु निर्यात भी 2014–15 के 310 अरब डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 442 अरब डॉलर हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए मंत्रालय ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें 47 प्रक्रियाओं का सरलीकरण, स्वचालित एफटीपी (विदेश व्यापार नीति) प्रक्रियाएं, आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) का स्वतरू सत्यापित रूप से जारी होना और निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत शामिल है।

संक्षिप्त

इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप के झटकों से दहले लोग, एक मिनट तक कांपती रही धरती

जकार्ता इंडोनेशिया के कई हिस्सों में मंगलवार को 6.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती झटके इतने तेज थे कि जमीन एक मिनट से अधिक समय तक हिलती रही, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी प्रांत की राजधानी च्सन से लगभग 46 किलोमीटर पूर्व–दक्षिण–पूर्व में स्थित था। भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप के झटके आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए, जिसके बाद लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी बड़े नुकसान, जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। गौरतलब है कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रियता के कारण अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं।

मेरी छवि खराब की जा रही है... 36 लाख फॉलोअर्स वाले फेसबुक पेज पर भड़के सौरव गांगुली, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

कोलकाता भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक फेसबुक पेज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गांगुली का आरोप है कि उनके नाम से फेसबुक फैन पेज पर लगातार ऐसी पोस्ट शेयर की जा रही है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। जानकारी के मुताबिक, शिकायत का केंद्र सौरव गांगुली फैंस नाम का फेसबुक पेज है। गांगुली का कहना है कि इस पर पोस्ट की गई कई पोस्ट उनकी छवि को खराब व गलत दिखा रही हैं। इस पेज के 36 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिससे इसकी पहुंच काफी बड़ी है। कोलकाता के ठाकुरपुकुर थाने में दर्ज शिकायत में गांगुली ने मांग की है कि पेज का चलाने वाले लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

एफआईएच महिला नेशंस कप: भारत ने जापान को 2–1 से हराया, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम

एजेंसी

ऑकलैंड। भारत ने मंगलवार को एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2026 में पूल (ए) के अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 2–1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने अब तक अपने दोनों पूल मैच जीते हैं। ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में खेले गए मुकाबले में कप्तान और प्लेयर ऑफ द मैच सलीमा टेटे (33वें मिनट) और लालरेमसियामी (49वें मिनट) ने भारत के लिए गोल दागे, जबकि एई हिरामित्सु (35वें मिनट) जापान की एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं। मिडफील्डर ज्योति के लिए यह एक यादगार मैच था, जिन्होंने अपना

100वां सीनियर इंटरनेशनल मैच खेला। पहला हाफ बेहद कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन हाफ–टाइम तक कोई भी टीम बराबरी नहीं तोड़ सकी। तीसरे क्वार्टर में खेल में तब रोमांच आ गया जब भारत ने 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर में अपना पहला गोल किया। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने बेहतरीन तरीके से सलीमा की ओर पास किया और कप्तान ने उसे गोल में तब्दील कर भारत को बढ़त दिलाई। हालांकि जापान ने 2 मिनट बाद ही मैच में पकड़ बना ली। हिरामित्सु (35वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागकर बराबरी कर ली। अंतिम क्वार्टर में भारत की लालरेमसियामी ने 49वें मिनट में विजयी गोल दागा। सुशीला चानू पुखरामबम ने सर्कल के किनारे से गोल की ओर एक सटीक पास दिया और लालरेमसियामी को गेंद को नेट में डालकर भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ, अपराजित भारत, अमेरिका और जापान के खिलाफ जीत से मिले छह अंकों के साथ पूल (ए) में शीर्ष पर पहुंच गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743